विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ऊर्जा गांव अथवा ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम सातवीं योजना में शुरू किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रदर्शन ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं, जो विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों तथा प्रणालियों के संयोजन पर आधारित हैं, ऊर्जा सर्वेक्षणों के जरिए निर्धारित गांवों में शुरू की जाती हैं ।

(ख) इस प्रदर्शनकार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं । 1990-91 के दौरान, शुरू की जाने वाली प्रस्तावित 25 ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं की तुलना में 33 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में वास्तव में पूरी कर ली गई थीं ।

(ग) और (घ) ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं आजमगढ़ में गांव सिकौरा, मउ में गांव पतराव, गाजीपुर में गांव रसूलपुर, जौनपुर में गांव हरद्वारी और सुलतानपुर में गांव माझवारा, भाण्डर कोहरा और कौहर (बाजार) में उत्तर प्रदेश के लिए नोडल अभिकरण द्वारा शुरू की गई हैं । इन परियोजनाओं में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों जैसे उन्नत चूल्हों, बायोगैस संयंत्रों, सौर कुकरों, सौर जल हीटरों, सौर स्टिलों, सौर प्रकाश-वोल्टीय लाइटों, पम्पों तथा टेलीविजन पवन पम्पों इत्यादि की विशिष्ट संयोजनों के साथ स्थापना शामिल है जो स्थानीय साधनों पर निर्भर है ।

Panel of experts on Tehri Dam Project

465. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to appoint an inter-disciplinary panel of experts including seismologists, to look afresh into the Tehri Dam Project to remove all doubts from the view-point of future safety of the Dam as per the suggestion contained in the Editorial entitled "Have another look at Tehri", which appeared in Hindustan Times of 21st October, 1991;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) The safety aspects of the Tehri Dam vis-a-vis seismicity of the region have been examined through a High Level Committee of Experts. The Committee, which included top level Specialist Scientists and Engineers in the connected fields, have after going into matter and after assuming the worst earthquake scenario concluded that the Tehri Dam Projects as proposed would be safe. All dangers arising out of seismicity have been taken into account in the planning of the Tehri Dam Project.

Since the design of the dam has been found to be safe for the intensity of earthquake expected in the region, re-examination of its safety aspects does not arise.

Private Sectors participation in power generation

466. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news item that appeared in the 'Business and Political Observer' of the 18th October, 1991 regarding a note alleged to have been sent by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry asking for further

steps by Government for facilitating private sectors' participation in power generation; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes Sir. Comments have been received from a large number of Chambers of Commerce, Trade Bodies, both in India and abroad. Clarifications are being provided during discussions with these bodies. A brochure has been brought out giving details of the scheme to encourage private sector participation in power generation, supply and distribution field, which has been widely circulated.

Amount sanctioned for expansion of power distribution system in Madhya Pradesh

467. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER AND CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have sanctioned any amount for expansion of power distribution system in Madhya Pradesh recently; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) An outlay of Rs. 104.05 crores was approved by Planning Commission for distribution works of Madhya Pradesh Electricity Board for the year 1991-92, details of which are given below:—

(i) Normal Development works.....Rs. 85.05 crorse
(ii) System Improvement works and Capacitor installation..... Rs. 19.00 crores

In addition, an mount of Rs. 6 crores has been allocated for renovation and modernisation of Transmission and Distribution works in Madhya Pradesh.

कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

468. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ गैर-सरकारी उपक्रमों को विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार के पास ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचारार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ग) गैर-सरकारी उपक्रमों को दी जाने वाली प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(घ) महाराष्ट्र में कौन-कौन से गैर-सरकारी उपक्रमों को ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार इन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर निष्पादित करने की कोई शर्त रखने का विचार रखती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां । विद्युत की बढ़ती हुई मांग और इसकी सप्लाई में कमी के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु विद्युत क्षेत्र में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत विद्युत के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण में निजी क्षेत्र उद्यमों द्वारा और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) 8 (आठ) आवेदन लम्बित हैं।